



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक संवत्) [संख्या 16

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	425—452	3075	भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	227—244	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐकट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
	..		(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
	..		भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐकट		975
	..		भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	95—110	
	..		भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के ऑकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के ऑकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	165—166	975
	..	975	स्टोस—पचेज विभाग का क्रोड पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-2

कार्यालय -आदेश

07 जनवरी, 2022 ई०

सं० 14 /छःपु०से०-२-२२-५४७(१) /२०१५—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के वर्ष २०१३ बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-४ में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे-मैट्रिक्स का लेवल-१२ रु० ७८,०००—२,०९,२००) इस शर्त के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिन अधिकारियों द्वारा मैनडेटरी मिड कैरियर-III (एमटीसीपी-III) प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया गया है, उनके द्वारा उक्त प्रशिक्षण यथासमय कर लिया जायेगा—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	बैच	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
सर्वश्री / श्रीमती—			
1	आशीष श्रीवास्तव	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
2	अनुराग वत्स	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
3	आकाश तोमर	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
4	अनुराग आर्य	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
5	डा० अभिषेक महाजन (अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर)	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
6	डा० गौरव ग्रोवर	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
7	सुनीति	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
8	ख्याति गर्ग	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
9	रोहित सिंह सजवान	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
10	अमित कुमार-I	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
11	डा० सतीश कुमार	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
12	डा० यशवीर सिंह	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
13	श्री गणेश प्रसाद साहा	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
14	कुँवर अनुपम सिंह	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
15	सिद्धार्थ शंकर मीना	आईपीएस-आरआर-2013	01-01-2022
16	राम यज्ञा	आईपीएस-एसपीएस-2013	01-01-2022
17	अरविन्द कुमार मौर्य	आईपीएस-एसपीएस-2013	01-01-2022
18	तेज स्वरूप सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2013	01-01-2022
19	सुभाष चन्द्र शाक्य	आईपीएस-एसपीएस-2013	01-01-2022

07 जनवरी, 2022 ई०

सं० 15 / छःपु०से०-२-२२-५४७(१) / १९९२—भारतीय पुलिस सेवा (उ०प्र० संवर्ग) के वर्ष २०१८ बैच के सीधी भर्ती के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सम्मुख कालम-४ में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का वरिष्ठ समयमान वेतनमान (पे-मैट्रिक्स का लेवल-११ रु० ६७,७००—२,०८,७००) इस शर्त के अधीन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जिन अधिकारियों द्वारा फाउण्डेशन कोर्स पूर्ण नहीं किया गया है, उनके द्वारा फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण यथासमय कर लिया जायेगा—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	बैच	वरिष्ठ समयमान वेतनमान अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
सर्वश्री / श्रीमती—			
1	साद मियां खां	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
2	पलाश बंशल	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
3	सूरज कुमार राय	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
4	अभिमन्यु मांगलिक	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
5	सैयद अली अब्बास	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
6	अंकिता शर्मा	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
7	राहुल भाटी	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
8	अनिल कुमार यादव	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
9	सन्तोष कुमार मीना	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
10	लखन सिंह यादव	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
11	मनीष कुमार शांडिल्य	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
12	कृष्ण कुमार	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
13	अविजीथ आर० शंकर	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
14	अभिषेक भारती	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
15	सन्दीप कुमार मीना	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022
16	अनिरुद्ध कुमार	आईपीएस-आरआर-2018	01-01-2022

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

09 जनवरी, 2022 ई०

सं० 17डीजी / छःपु०से०-२-२२-पी०एफ०-८ / ०३(ए)—श्री असीम कुमार अरुण, आईपीएस-आरआर-1994, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा पत्र संख्या-सीए / सीपी-३३ / २०२२, दिनांक ०८ जनवरी, २०२२ द्वारा अखिल भारतीय सेवा (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स) नियमावली-१९५८ के नियम-१६(२) के अन्तर्गत उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के पूर्व निजी कारणों से दिनांक १५ जनवरी, २०२२ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए आवेदन किया गया है।

श्री असीम कुमार अरूण, आईपीएस-आरआर-1994, की दिनांक 02 जनवरी, 1995 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त हुई थी। उनकी जन्मतिथि 03-10-1970 है। इस प्रकार श्री अरूण द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है। श्री अरूण के प्रार्थना-पत्र में किये गये अनुरोध एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री असीम कुमार अरूण, आईपीएस-आरआर-1994, पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने में हुये विलम्ब को मर्षित करते हुए उनको सेवा पूर्ण होने के पर्व दिनांक 15 जनवरी, 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

कुमार प्रशान्त,

विशेष सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-13

औपबंधिक नियुक्ति

03 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1551/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमर जीत पुत्र श्री जंग बहादुर पटेल का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

65	अमर जीत/जंग	14-09-1993	107347	प्रयागराज जंग बहादुर पटेल, अमर जीत रुम नं0 बहादुर पटेल	27 मङ्गियारी ताओ बी0 640 राजीव चटौना, सराय भवन, आईआईटी ममरेज, प्रयागराज, रुड़की, रुड़की, उ0प्र0-212402 उत्तराखण्ड- 247667	
----	-------------	------------	--------	---	---	--

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1552 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री विकास छाज्याण पुत्र श्री सोमेश्वर का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

66	विकास छाज्याण/ सोमेश्वर	12-11-1997	113784	गाजियाबाद सोमेश्वर, स्कूल के पीछे, दिल्ली सहारनपुर रोड़ गाजियाबाद, उ0प्र0-201102	ए-45, 1रामपार्क हिमालयन स्कूल के पीछे, दिल्ली सहारनपुर रोड़ गाजियाबाद, उ0प्र0-201102	सोमेश्वर, 1रामपार्क हिमालयन स्कूल के पीछे, दिल्ली सहारनपुर रोड़ गाजियाबाद, उ0प्र0-201102
----	-------------------------------	------------	--------	--	---	---

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1553 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ वर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द्र वर्मा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

67	सौरभ वर्मा/ दिनेश चन्द्र वर्मा	02-07-1996	86981	बाराबंकी	सौरभ दीनदयाल नाका बाराबंकी, 225001	वर्मा, नगर, नाका पैसार, बाराबंकी, उ0प्र0- 225001	सौरभ दीनदयाल नाका पैसार, बाराबंकी, उ0प्र0-
----	--------------------------------	------------	-------	----------	------------------------------------	--	--

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-

पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1554 /सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आकाश सिंह पुत्र श्री जय प्रकाश सिंह का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभुक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	---------

सर्वश्री—

68	आकाश सिंह/ जय प्रकाश सिंह	18-10-1994	48387	जौनपुर	जय प्रकाश सिंह, जय प्रकाश सिंह, जमुनीबारी, चंदवक, जमुनीबारी, चंदवक, जौनपुर, उ0प्र0- 222129	जौनपुर, उ0प्र0- 222129
----	---------------------------	------------	-------	--------	--	------------------------

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1555 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिवम प्रजापति पुत्र श्री सुनील कुमार का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

69	शिवम प्रजापति / सुनील कुमार	28-07-1995	44902	मेरठ	सुनील म0न0-572, नं0-7, मुल्ताननगर,	कुमार, स्ट्रीट रोड, मेरठ,	सुनील कुमार, म0न0- 572, स्ट्रीट रोड, मुल्तान- नगर, मेरठ, उ0प्र0-250002 250002
----	--------------------------------	------------	-------	------	---	------------------------------------	--

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत

सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1556/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सद्दाम हुसेन पुत्र श्री सुल्तान अली का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
70	सद्दाम हुसेन/ सुल्तान अली	11-07-1993	80500	महाराजगंज	सुल्तान कतरारी, पीपरपाती, महाराजगंज, उ0प्र0- 273306	अली, कतरारी, पीपरपाती, महाराजगंज, उ0प्र0- 273306	सुल्तान अली, कतरारी, पीपरपाती, महाराजगंज, उ0प्र0-

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1557 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आशुतोष पाण्डेय पुत्र श्री बजरंगी प्रसाद पाण्डेय का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
71	आशुतोष पाण्डेय / बजरंगी पाण्डेय	06-02-1997	1730	गोण्डा	बजरंगी पाण्डेय, गोण्डा,	प्रसाद नौबस्ता, उ0प्र0- 271124	बजरंगी पाण्डेय, कालोनी, लालगंज प्रतापगढ़, उ0प्र0- 230132

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के

अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

- [I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
- [II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
- [III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
- [IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1558 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री इमरान खान पुत्र श्री कलामुददीन खान का विवरण निम्नवत् हैं—

क्र०	नाम/पिता	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	का नाम			जनपद			

सर्वश्री—

72	इमरान खान/ 05-10-1996	14053	मिर्जापुर	इमरान खान 59,	इमरान खान 59,		
	कलामुददीन			ग्राम व पौ० भुरकुरा,	ग्राम व पौ० भुरकुरा,		
	खान			मिर्जापुर,	उ०प्र०-	मिर्जापुर,	उ०प्र०-
				231304		231304	

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु० 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

- [I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
- [II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
- [III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
- [IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1559/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री श्रद्धेश चन्द्र पुत्र श्री मनोज कुमार का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

73	श्रद्धेश चन्द्र/ मनोज कुमार	01-09-1994	71922	लखनऊ	श्रद्धेश चन्द्र, म0न0-369, इन्दिरा लखनऊ,	श्रद्धेश चन्द्र, म0न0-369, इन्दिरा नगर, उ0प्र0-226016
----	-----------------------------	------------	-------	------	---	--

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र।

सं0 1560 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शिवानंद मिश्रा पुत्र श्री परमानन्द मिश्रा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
74	शिवानंद मिश्रा/ परमानन्द मिश्रा	11-06-1996	54702	गोरखपुर	शिवानंद मिश्रा C/o परमानन्द मिश्रा, 44ए, महादेव झारखण्डी टुकडा नं0 1, शिवपुर गोरखपुर, 273008	शिवानंद मिश्रा C/o परमानन्द मिश्रा, 44ए, महादेव झारखण्डी टुकडा नं0 1, शिवपुर कूडाघाट, उ0प्र0-273008	

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1561 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री आदित्य कुमार पुत्र श्री राम दयाल का विवरण निम्नवत् है—

क्र०	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

75	आदित्य कुमार/ 17-09-1993	117046	सुल्तानपुर राम दयाल, टिहरा राम दयाल, टिहरा	द्वारकागंज, सुल्तान-पुर, उ० प्र०-	द्वारकागंज, सुल्तान-पुर, उ० प्र०-	228125
	राम दयाल			उ०	प्र०-	228125

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु० 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी ।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी ।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी ।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे ।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक

रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1562/सत्ताईस-13-2021-49/21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री राजन यादव पुत्र श्री मस्तराम यादव का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

76	राजन यादव/ मस्तराम यादव	20-12-1994	124798	चन्दौली	मस्तराम यादव, रोहित नेत्रालय, खरौझा कम्पलेक्स, शमशेर नगर, चन्दौली, उ0प्र0-	रोहित नेत्रालय, खरौझा कम्पलेक्स, शमशेर नगर, चन्दौली, उ0प्र0- 232103
----	-------------------------	------------	--------	---------	--	---

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल

समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रामाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1563/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सरजू प्रसाद पुत्र श्री कालिका प्रसाद का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अन्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

77	सरजू प्रसाद/ कालिका प्रसाद	16-08-1993	28541	सुल्तानपुर	कालिका प्रसाद, पूरे लाला, डोभियारा, सुल्तानपुर, उ0प्र0-	कालिका प्रसाद, पूरे लाला, डोभियारा, सुल्तानपुर, उ0प्र0-
					227815	227815

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1564/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री वसीम अहमद पुत्र श्री सलीम अहमद का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	का नाम			जनपद			

सर्वश्री—

78	वसीम अहमद/ 22-01-1998 109665 बागपत	वसीम अहमद,	वसीम अहमद,
	सलीम अहमद	लालीयान, ग्राम व	लालीयान, ग्राम व
		पो0 लालीयान,	पो0 लालीयान,
		जनपद बागपत,	जनपद बागपत,
		उ0प्र0-250515	उ0प्र0-250515

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्ति किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1565 /सत्ताईस-13-2021-49 /21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री शिवदत्त का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
	का नाम			जनपद			
सर्वश्री—							
80	सत्य प्रकाश/ शिवदत्त	15-07-1995	47021	बांदा	सत्य प्रकाश C/o शिव सत्य प्रकाश C/o शिव दत्ता, ए-202, आवास दत्ता, ए-202, आवास विकास कालोनी, बांदा, विकास कालोनी, बांदा,		उ0प्र0-210001

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र / कार्यमुक्ति किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा संशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रामाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1566 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सर्वेश कुमार यादव पुत्र श्री राजेन्द्र यादव का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
सर्वश्री—							
81	सर्वेश कुमार यादव/राजेन्द्र यादव	13-02-1993	33981	गाजीपुर	राजेन्द्र यादव, 135 कवला, जखनियां, जखनियां, गाजीपुर, उ0प्र0-275203	राजेन्द्र यादव, 135 कवला, जखनियां, जखनियां, गाजीपुर, उ0प्र0-275203	

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्ति किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक

रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्राणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं० 1567 /सत्ताईस-13-2021-49 /21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अश्वनी मिश्रा पुत्र श्री योगेन्द्र नाथ मिश्रा का विवरण निम्नवत् है—

क्र०	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

82	अश्वनी मिश्रा/ योगेन्द्र नाथ मिश्रा	03-06-1989	13110	कौशाम्बी	अश्वनी मिश्रा, ग्राम बैरामपुर, बैरामपुर, कौशाम्बी, उ०प्र०-212214	अश्वनी मिश्रा, 582 पो० कृष्ण बाग कालोनी, प्रेस काम्पलेक्स के पीछे, इन्दौर, मध्य प्रदेश-452010
----	-------------------------------------	------------	-------	----------	--	---

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु० 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु० 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1568/सत्ताईस-13-2021-49/21-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री मोहम्मद उमर खान पुत्र श्री रईसउल्लाह खान का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

83	मोहम्मद	उमर	07-08-1996	79695	गाजियाबाद	मोहम्मद	उमर
					एम-261बी,	संजय	खान, एम-261बी,
	खान/				नगर, सेक्टर	23,	संजय नगर, सेक्टर
	रईसउल्लाह				गाजियाबाद, उ0प्र0-	23,	गाजियाबाद,
	खान				201002		उ0प्र0-201002

2—शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्त हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भांति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-पत्र / कार्यमुक्ति किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रामाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

[I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।

[II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।

[III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।

[IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

सं0 1569 / सत्ताईस-13-2021-49 / 21—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर सहायक अभियन्ता (सिविल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सीधी भर्ती के रिक्त पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अमन राज वर्मा पुत्र श्री राज कुमार वर्मा का विवरण निम्नवत् है—

क्र0	नाम/पिता का नाम	जन्म-तिथि	अनुक्रमांक	गृह जनपद	स्थाई पता	पत्र-व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
------	--------------------	-----------	------------	-------------	-----------	---------------------	-----------

सर्वश्री—

84	अमन राज	04-06-1997	102207	सुल्तानपुर	अमन राज वर्मा, वर्मा/राज कुमार वर्मा	अमन राज वर्मा, 155 के महिलो आशापुर कनौली, सुल्तानपुर, उ0प्र0-	अमन राज वर्मा, 155 के महिलो आशापुर कनौली, सुल्तानपुर, उ0प्र0-228125
----	---------	------------	--------	------------	--------------------------------------	---	---

2—शासनादेश संख्या 04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड रु0 15,600-39,100 (ग्रेड पे रु0 5,400) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 में 02 वर्ष की परिवीक्षा पर औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) अभ्यर्थी को उक्त औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबंधिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(2) यह नियुक्ति नितान्त औपबंधिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(3) उक्त अभ्यर्थी को अपना कार्यभार, इस आदेश के निर्गत होने के एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति/पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(5) उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(6) नवचयनित सहायक अभियन्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

(7) अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के संबंधित अधिकारी यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कहीं कार्यरत रहा हो तो उनके द्वारा तकनीकी त्याग-

पत्र/कार्यमुक्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार किये जायें। उक्त के साथ ही औपबंधिक रूप से चयनित जिन अभ्यर्थियों की आयोग द्वारा सशर्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C.) उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये। इसी के साथ शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्रों में सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जाये।

(8) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेंगे—

- [I] केवल एक जीवित पत्नी होने का प्रमाण-पत्र ।
- [II] अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण ।
- [III] राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की 02 फोटो ।
- [IV] अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया सत्यापन-पत्र एवं स्वःघोषणा-पत्र ।

आज्ञा से,
फूल चन्द्र,
संयुक्त सचिव ।



सरकारी गज़ाट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञाप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[ADMIN. 'G-II' SECTION]

NOTIFICATION

April 11, 2022

No. 159/2022, Allahabad—In compliance of the directions issued by Hon'ble Supreme Court vide Judgment dated 11.01.2022 passed in Miscellaneous Application No. 1852 of 2019 in Criminal Appeal No. 1101 of 2019, Smruti Tukaram Badade Vs State of Maharashtra & Anr., the High Court of Judicature at Allahabad is pleased to make the following scheme i.e. “Vulnerable Witnesses Deposition Centres Scheme 2022” for Subordinate Courts of Uttar Pradesh, which shall come in to force with immediate effect.

VULNERABLE WITNESSES DEPOSITION CENTRES SCHEME 2022

Whereas The Hon'ble Supreme Court of India in *State of Maharashtra Vs. Bandu @ Daulat; (2018) 11 SCC 163* has issued certain directions for setting up Special Centres for examination of vulnerable witnesses in criminal cases so as to facilitate the conducive environment for recording statement of such witnesses and issued directions to all the High Courts to adopt the guidelines framed in this regard by the Delhi High Court with requisite modifications and also keeping in view the judgment dated 11.01.2022 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in *Smruti Tukaram Badade Versus State of Maharashtra and Another; Misc. Application No. 1852 of 2019 In Re: Criminal Appeal No. 1101 of 2019* whereby certain directions were issued to all the High Courts pertaining to the establishment, functioning and framing of scheme/guidelines for the establishment and functioning of Vulnerable Witnesses Deposition Centres, following scheme is promulgated/adopted in order to regulate the recording of evidence of the vulnerable witnesses in criminal cases.

OBJECTIVES OF THE SCHEME

1. To elicit and secure complete, accurate and reliable evidence from vulnerable witnesses;
2. to minimize harm or secondary victimization of vulnerable witnesses in anticipation and as a result of participation in the criminal justice system;
3. to ensure that the accused's right to a fair trial is also maintained.

Applicability

Unless otherwise provided, this scheme shall govern the examination of vulnerable witnesses during criminal trial, who are victims or witnesses of crime.

1. Short Title, extent and commencement.-

This scheme shall be called 'Vulnerable Witnesses Deposition Centre Scheme-2022'. It will apply to all criminal courts in Uttar Pradesh subordinate to The High Court of Judicature at Allahabad. The Scheme shall come into operation w.e.f. the date notified by the High Court of Judicature at Allahabad.

2. Construction of the scheme.-This scheme shall be liberally construed to uphold the interests of vulnerable witnesses and to promote their maximum accommodation without prejudice to the right of the accused to a fair trial.

3. Definitions.-

a. **Vulnerable Witness** – Following witnesses shall be regarded as vulnerable witness:-

- I. A witness who has not attained 18 years of age.
- II. Victims of offences under Sections 354 and 377 IPC.
- III. Victims of offences under Sections 376, 376A, 376B, 376C and 376D IPC.
- IV. Victims of offences defined under The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
- V. Witnesses suffering from "mental illness" as defined under Section 2(S) of the Mental Healthcare Act, 2017 read with Section 118 of the Indian Evidence Act, 1872.
- VI. Any speech or hearing impaired person suffering from any other disability rendering such persons, in the opinion of the court, as vulnerable witness.
- VII. Any witness deemed to have a threat perception under the Witness Protection Scheme, 2018 of the Central Government.
- VIII. Any other victim or witness deemed to be vulnerable by the concerned court.

b. **Support Person** - Means and includes guardian *ad litem*, legal aid lawyer, facilitators, interpreters, translators and any other person appointed by court or any other person appointed by the court to provide support, accompany and assist the vulnerable witness to testify or attend judicial proceedings.

c. **In-Camera Proceedings** - Means proceedings pertaining to criminal matters or parts thereof wherein the public generally or any particular person may not be allowed to participate, for good reason as provided u/s 327 of the Code of Criminal Procedure.

d. **Concealment of Identity of witness** - Means and includes any condition prohibiting publication of the name, address and other particulars of the vulnerable witness, which may lead to the identification of the witness.

e. **Comfort Items** - Comfort items mean any article which shall have a calming effect on a vulnerable witness at the time of deposition.

f. **Competence of a Vulnerable Witness** - Every vulnerable witness shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving

rational answers to those questions due to tender age, disease, either of body or mind, or any other cause of the same kind.

Explanation: A mentally ill person may also be held competent unless he/she is prevented by his/her lunacy to understand questions.

- g. **Court House Tour** - A pre-trial tour of court room to familiarize a vulnerable witnesses with the environment and the basic process of adjudication and roles of each court official.
 - h. **Descriptive Aids** - A human figure model, anatomically correct dolls or a picture or anatomical diagrams or any other aids deemed appropriate to help a vulnerable witness to explain an act or a fact.
 - i. **Live-Link** - 'Live-link' means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangement whereby a witness, while absent from the courtroom is nevertheless present in the court room by remote communication using technology to give evidence and be cross-examined.
 - j. **Special Measures** - Means and includes the use of any mode, method and instrument etc. considered necessary for providing assistance in recording deposition of vulnerable witnesses.
 - k. **Testimonial Aids** - Means and includes screen; live-links, image and/or voice altering devices; or any other technical devices.
 - l. **Secondary Victimization** - Means victimization that occurs not as direct result of a criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim.
 - m. **Revictimization** - Means a situation in which a person suffers more than one criminal incident over a period of time.
 - n. **Waiting Room** - A safe place for vulnerable witnesses where they can wait. It may have toys, books, T.V. etc. which can help in lowering the anxiety of such witnesses.
4. **Special Measures.-** The court may direct as to which, special measure will be used to assist a particular eligible witness in providing the best evidence.
5. **Applicability of Scheme to all Vulnerable Witnesses.-**

For the avoidance of doubt, it is made clear that this scheme shall apply to all vulnerable witnesses, regardless of which party is seeking to examine the witness.

6. **No adverse inference to be drawn from special measures.-**

The fact that a witness has had the benefit of a special measure to assist them in deposition, shall not be regarded in any way whatsoever as being adverse to the position of the other side and this should be made clear by the Judge at the time of passing order in terms of this scheme to the parties when the vulnerable witness is examined and when the final judgment is pronounced.

7. **Identification of stress causing factors of adversarial Criminal Justice System.-**

Factors which cause stress on vulnerable witness, rendering them further vulnerable and impeding complete disclosure by them shall, amongst others, include:

- (i) **Using in appropriate language during examination in chief, cross examination or re examination.**
- (ii) Delays and continuances.
- (iii) Testifying more than once.
- (iv) Prolonged/protracted hours of court proceedings.
- (v) Lack of communication between professionals including police, doctors, lawyers, prosecutors, investigators, psychologists etc.
- (vi) Fear of public exposure.

- (vii) Lack of understanding of complex legal procedures.
- (viii) Face-to-face contact with the accused.
- (ix) Practices which are insensitive to developmental needs.
- (x) Inappropriate and prolonged cross-examination.
- (xi) Lack of adequate support and victims services.
- (xii) Sequestration of witnesses who may be supportive to the child.
- (xiii) Placement that exposes the vulnerable witness to intimidation, pressure, or continued abuse.
- (xiv) Inadequate preparation for fearless and robust testifying.
- (xv) Worry about not being believed especially when there is no evidence other than the testimony of the vulnerable witness.
- (xvi) Formalities of court proceedings and surroundings including formal dress of members of the judiciary and legal personnel.

8. Competency of Vulnerable Witness.-

- (i) Every vulnerable witness shall be presumed to be qualified as a witness unless prevented by the following:
 - (a) Age.
 - (b) Physical or mental disability leading to recording a finding of doubt regarding the ability of such witness to perceive, remember, communicate, distinguish truth from falsehood or appreciate the duty to tell the truth, and/or to express the same.

Explanation: The court shall conduct a competency assessment before recording the testimony of such witness on an application of either prosecution or defence or *suo motu*.

9. Persons allowed at competence assessment.-

Only the following, in the discretion of the court, may be allowed to attend the competence assessment:

- (i) The Judge and such court personnel deemed necessary and specified by order of the Judge concerned;
- (ii) the counsel for the parties;
- (iii) the guardian *ad litem*;
- (iv) one or more support persons for the child; and
- (v) the accused, unless the court determines that competence requires to be and can be fully evaluated in his absence.

- (vi) Any other person, who in the opinion of the court can assist in the competence assessment.

10. Conduct of competence assessment.-

The assessment of a child as to his/her competence as a witness shall be conducted only by the Judge.

11. Developmentally appropriate questions.-

The questions which may be asked to assess the competency of the vulnerable witness shall be appropriate and commensurate to the age and developmental level of the vulnerable witness; shall not be related to the issues at trial; and shall focus on the ability of the vulnerable witness to remember, communicate, distinguish between truth and falsehood and appreciate the duty to testify truthfully.

12. Continuing duty to assess competence.-

The court shall have a duty of continuously assessing the competence of the vulnerable witnesses throughout their testimony and to pass appropriate orders, as and when deemed necessary.

13. Pre-trial visit of Witnesses to the Court.-

Vulnerable witness shall be allowed a pre trial tour of the court, along with the support person to enable such witnesses to familiarize himself with the layout and atmosphere of the court; and may also include visit to and explanation of the following:

- (i) The location of the accused in the dock;
- (ii) court officials (what their roles are and where they sit);
- (iii) who else might be in the court, for example those in the public gallery;
- (iv) the location of the witness box;
- (v) a run-through of basic court procedure;
- (vi) the facilities available in the court;
- (vii) discussion of any particular fears or concerns with the intermediaries, Prosecutors and the Judge to dispel the fear, trauma and anxiety in connection with the prospective deposition at court; and
- (viii) demonstration of any special measures applied for, and granted, for example practising on the live-link and explaining who will be able to see them in the courtroom and showing the use of screens (where it is practical and convenient to do so).

14. Meeting with the Judge.-

The Judge may meet a vulnerable witness, *suo motu*, on reasons to be recorded or on an application of either party in the presence of the prosecution and defence counsels or in their absence as the case may be, before they give evidence, for explaining the court process in order to help them in understanding the procedure and giving their best evidence.

15. Appointment of Guardian *ad litem*.-

The court may appoint any person as guardian *ad litem* as per law to a witness who is a victim of, or a witness to a crime having regard to his/her best interests after considering the background of the guardian *ad litem* and his/her familiarity with the judicial process, social service programs, giving preference to the parents of the child, if qualified. The guardian *ad litem* may also be a member of bar/practicing advocate, except a person who is a witness or informant in any proceeding involving the vulnerable witness.

16. Duties of Guardian *ad litem*.-

It shall be the duty of the guardian *ad litem* so appointed by court to:

- (i) Attend all depositions, hearings, and trial proceedings in which a vulnerable witness participates.
- (ii) Make recommendations to the court concerning the welfare of the vulnerable witness keeping in view the needs and impact of the proceedings on such witness.
- (iii) Explain in the language understandable to the vulnerable witness, all legal proceedings, including police investigations, in which the witness is involved.
- (iv) Assist the vulnerable witness and his/her family in coping with the emotional effects of crime and subsequent criminal or non-criminal proceedings in which the witness is involved.
- (v) Remain with the vulnerable witness while the vulnerable witness waits to testify.

17. Legal assistance.-

A vulnerable witness may be provided with legal assistance by the court either at the request of the support person, if one has been designated or pursuant to an order of the court on its own motion, if the court considers the assignment of a lawyer to be in the best interests of the vulnerable witness, throughout the trial.

18. Court to allow presence of support persons.-

- (a) A court shall allow *suo motu* or on request, verbal or written, of the vulnerable witness testifying at a judicial proceeding to have the presence of one person of his own choice to provide him support who shall remain within his/her view and if the need arise may accompany such witness to witness stand, provided that such support person shall not completely obscure the child from the view of the opposing party or the Judge.
- (b) The court may allow the support person to hold the hand of the vulnerable witness or take other appropriate steps to provide emotional/moral support to the vulnerable witness in the course of the proceedings.
- (c) The court shall instruct the support persons not to prompt, sway, or influence the vulnerable witness during his/her testimony. The support person shall also be directed that he/she shall under no circumstances discuss the evidence to be given by the vulnerable witness.

19. The testimony of support person to be recorded prior.-

A testimony of the support person, if he/she also happens to be a witness, shall be recorded, ahead of the testimony of the vulnerable witness.

20. Court to appoint facilitator.-

- (i) To assist the vulnerable witnesses in effectively communicating at various stages of trial and or to coordinate with the other stake holders such as police, medical officer, prosecutors, psychologists, defence counsels and courts, the court may allow use of facilitators.
- (ii) The court may, *suo motu* or upon an application presented by either party or a support person of vulnerable witnesses may appoint a facilitator, if it determines that such witness is finding it difficult to understand or respond to questions asked.

Explanation: (i) The facilitator may be an Interpreter, a Translator, Child Psychologist, Psychiatrist, Social Worker, Guidance Counselor, Teacher, Parent, or relative of such witness who shall be under oath to pose questions according to meaning intended by the counsel.

(ii) If the court appoints a facilitator, the respective counsels for the parties shall pose questions to the vulnerable witness only through the facilitator, either in the words used by counsel or, if the vulnerable witness is not likely to understand the same, in words or by such mode as is comprehensible to the vulnerable witness and which convey the meaning intended by counsel.

21. Right to be informed.-

A vulnerable witness, his or her parents or guardian, his or her lawyer, the support person, if designated, or other appropriate person designated to provide assistance shall, from their first contact with the court process and throughout that process, be promptly informed by the court about the stage of the process and, to the extent feasible and appropriate, about the following:

- (a) Procedures of the criminal justice process including the role of vulnerable witnesses, the importance, timing and manner of testimony, and the ways in which proceedings will be conducted during the trial;
- (b) existing support mechanisms available for a vulnerable witness when participating in proceedings, including making available appropriate person designated to provide assistance;

- (c) specific time and places of hearings and other relevant events;
- (d) availability of protective measures;
- (e) relevant rights of child victims and witnesses pursuant to applicable laws, the Convention on the Rights of the Child and other international legal instruments, including the Guidelines and the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, adopted by the United Nations General Assembly in its resolution 40/34 of 29 November 1985;
- (f) the progress and disposition of the specific case, including the apprehension, arrest and custodial status of the accused and any pending changes to that status, the prosecutorial decision and relevant post-trial developments and the outcome of the case.

22. Language, interpreter and other special assistance measures.-

- (a) The court shall ensure that proceedings relevant to the testimony of a vulnerable witness or victim are conducted in a language that is simple and comprehensible to such witness.
- (b) If a witness needs the assistance of interpretation into a language or mode that he/she understands, an interpreter may be provided, free of charge.
- (c) If, in view of the age, level of maturity or special individual needs, which may include but are not limited to disabilities if any, ethnicity, poverty or risk of revictimization, the child requires special assistance measures in order to testify or participate in the justice process, such measures may be provided free of cost.

23. Waiting area for Vulnerable Witness.-

The courts shall ensure that a waiting area for vulnerable witnesses with the support person, lawyer of the witness facilitation, if any, is separate from waiting areas used by other persons. The waiting area for vulnerable witnesses should be furnished so as to make a vulnerable witness comfortable.

24. Duty to provide comfortable environment.-

It shall be the duty of the court to ensure comfortable environment for the vulnerable witness by issuing suitable directions and also by supervising, the location, movement and deportment of all persons in the courtroom including the parties, their counsels, witnesses, support persons, guardian *ad litem*, facilitator, and court personnel. The witness may be allowed to testify from a place other than the witness chair. The witness chair or other place from which the vulnerable witness testifies may be turned to facilitate his/her testimony but the opposing party and his/her counsel must have a frontal or profile view of the witness even by a video-link, during the recording of testimony of the such witness. The witness chair or other place from which the child testifies may also be rearranged to allow the child to see the opposing party and his/her counsel, if he/she chooses to look at them, without turning his/her body or leaving the witness stand. While deciding to make available such environment, the Judge may be dispensed with from wearing his judicial robe.

25. Testimony during appropriate hours.-

The court may order that the testimony of the vulnerable witness may be recorded at a particular time of the day within court hours, when the vulnerable witness is well-rested.

26. Recess during testimony.-

The vulnerable witness may be allowed reasonable periods of breaks while undergoing depositions as often as necessary depending on his developmental need.

27. Measures to protect the privacy and well-being of Vulnerable Witness and victims.-

- (1) At the request of the victim or vulnerable witness, his or her parents or guardian, his or her lawyer, the support person, other appropriate person designated to provide assistance, or the court on its own motion, taking into account the best interests of the witness, may order one or more of the following

measures to protect the privacy and physical and mental well-being of the vulnerable witness and to prevent undue distress and secondary victimization:-

- (a) Expunging from the public record any names, addresses, workplaces, professions or any other information that could be used to identify the witness;
 - (b) forbidding the defence lawyer and persons present in court room from revealing the identity of the witness or disclosing any material or information that would tend to identify the witness;
 - (c) ordering the non-disclosure of any records that identify the witness, until such time as the court may find appropriate;
 - (d) assigning a pseudonym or a number to a witness, in which case the full name and date of birth of the witness shall be revealed to the accused within a reasonable period for the preparation of his or her defence;
 - (e) efforts to conceal the features or physical description of the witness giving testimony or to prevent distress or harm to the witness, including testifying:
 - (i) behind screen;
 - (ii) using image-or voice-altering devices;
 - (iii) through examination in another place, transmitted simultaneously to the courtroom by means of video-link; and
 - (iv) through a qualified and suitable intermediary, such as, but not limited to, an interpreter for witness with hearing, sight, speech or other disabilities;
 - (f) holding closed sessions;
 - (g) if such witness refuses to give testimony in the presence of the accused or if circumstances show that the witness may be inhibited from speaking the truth in that person's presence, the court shall give orders to temporarily remove the accused from the courtroom to an adjacent room with a video-link or a one-way mirror visibility into the court room. In such cases, the defence lawyer shall remain in the courtroom and may question the witness, and the accused's right of confrontation shall thus be guaranteed; and
 - (h) taking any other measure that the court may deem necessary, including, where applicable, anonymity, taking into account the best interests of the witness and the rights of the accused.
- (2) Any information including name, parentage, age, address, etc. revealed by the victim or vulnerable witness which enables identification of the person of the witness, shall be kept in a sealed cover on the record and shall not be made available for inspection to any party or person. Certified copies thereof shall also not be issued. The reference to the child victim or vulnerable witness shall be only by the pseudonym assigned in the case.

28. Directions for Subordinate Court Judges.-

- (a) Vulnerable witnesses shall receive high priority and shall be handled as expeditiously as possible, minimizing unnecessary delays and continuances. (Whenever necessary and possible, the court schedule will be altered to ensure that the testimony of the vulnerable witness is recorded on sequential days, without delays).
- (b) Judges and court staff should ensure that the developmental needs of vulnerable witnesses are recognized and accommodated in the arrangement of the courtroom.

- (c) Separate and safe waiting areas and passage thereto should be provided for vulnerable witnesses.
- (d) Judges should ensure that the developmental stages and needs of vulnerable witnesses are identified recognized and addressed throughout the court process by requiring usage of appropriate language, by timing hearings and testimony to meet the attention span and physical needs of such vulnerable witnesses by allowing the use of testimonial aids as well as interpreters, translators, when necessary.
- (e) Judges should be flexible in allowing the vulnerable witnesses to have a support person present while testifying and should guard against unnecessary sequestration of support persons.
- (f) Hearings involving a vulnerable witness may be scheduled on days/time when the witness is not in inconvenienced or is not disruptive to routine/ regular schedule of such witness.

29. Allowing proceedings to be conducted in camera.-

- (a) When a vulnerable witness testifies, the court may order the exclusion from the courtroom of all persons, who do not have a direct interest in the case including members of the press. Such an order may be made to protect the right to privacy of the vulnerable witness, or if the court determines on the record that requiring the vulnerable witness to testify in open court would cause psychological harm to him, hinder the ascertainment of truth, or result in his inability to effectively communicate due to embarrassment, fear, or timidity.
- (b) In making its order, the court shall consider the developmental level of the vulnerable witness, the nature of the crime, the nature of his/her testimony regarding the crime, his/her relationship to the accused and to persons attending the trial, his/her desires, and the interests of his/her parents or legal guardian.
- (c) The court may, *motu proprio*, exclude the public from the courtroom if the evidence to be produced during trial is of such character as to be distressing, personal, offensive to decency or public morals.

30. Live-link television testimony in criminal cases where the Vulnerable Witness is involved.-

- (a) The prosecutor, counsel or the guardian *ad litem* may apply for an order that the testimony of the child be taken in a room outside the courtroom and be televised to the courtroom by live-link television.
- (b) In order to take a decision of usage of a live-link the Judge may question the child in chambers, or in some comfortable place other than the courtroom, in the presence of the support person, guardian *ad litem*, prosecutor, and counsel for the parties. The questions of the Judge shall not be related to the issues at trial but to the feelings of the child about testifying in the courtroom.
- (c) The court on its own motion, if deemed appropriate, may pass orders in terms of (a) or any other suitable directions for recording the evidence of a vulnerable witness.

31. Provision of screens, one-way mirrors, and other devices to facilitate Vulnerable Witness.-

The court may, *suo motu* or on an application made by the prosecutor or the guardian *ad litem*, order that the chair of the vulnerable witness or that a screen or other device be placed in the courtroom in such a manner that the child cannot see the accused while testifying. The court shall issue an order stating the reasons and describing the approved courtroom arrangement.

32. Factors to be considered while considering the application under Guidelines 30 & 31.-

The court may order that the testimony of the vulnerable witness be taken by live link television if there is a substantial likelihood that the vulnerable witness would not provide a full and candid account of

the evidence if required to testify in the presence of the accused, his/her counsel or the prosecutor as the case may be.

The order granting or denying the use of live-link television shall state the reasons therefore and shall consider the following:

- (a) The age and level of development of the vulnerable witness;
- (b) his/her physical and mental health, including any mental or physical disability;
- (c) any physical, emotional, or psychological harm related to the case on hand or trauma experienced by the witness;
- (d) the nature of the alleged offence and circumstances of its commission;
- (e) any threats against the vulnerable witness;
- (f) his/her relationship with the accused or adverse party;
- (g) his/her reaction to any prior encounters with the accused in court or elsewhere;
- (h) his/her reaction prior to trial when the topic of testifying was discussed with him by parents or professionals;
- (i) specific symptoms of stress exhibited by the vulnerable witness in the days prior to testifying;
- (j) testimony of expert or lay witnesses;
- (k) the custodial situation of the child and the attitude of the members of his/her family regarding the events about which he/she will testify; and
- (l) other relevant factors, such as court atmosphere and formalities of court procedure.

33. Mode of questioning.-

To facilitate the ascertainment of the truth the court shall exercise control over the examination-in-chief, cross-examination and re-examination of vulnerable witness in following manner-

- (a) Ensure that questions are stated in a form appropriate to the developmental level of the vulnerable witness;
- (b) protect vulnerable witness from harassment or undue embarrassment, prolong cross examination; and
- (c) avoid waste of time by declining questions which the court considers unacceptable due to their being improper, unfair, misleading, needless, repetitive or expressed in language that is too complicated for the witness to understand.
- (d) The court may allow the child witness to testify in a narrative form.
- (e) Questions shall be put to the witness only through the court.

34. Rules of and law with regard to the deposition to be explained to the Witnesses.-

The court shall explain to a vulnerable witness to listen carefully to the questions and to tell the whole truth, by speaking loudly and not to respond by shaking head in 'yes' or 'no' and also to specifically state that the witness does not remember where he/she has forgotten something and to clearly ask when the question is not understood.

A gesture by a child to explain what had happened shall be appropriately translated and recorded in the child's deposition.

35. Objections to questions.-

Objections to questions should be couched in a manner so as not to mislead, confuse, frighten a vulnerable witness.

36. Allow questions in simple language.-

The court shall allow the questions to be put in simple language avoiding slang, esoteric jargon, proverbs, metaphors and acronyms. The court must not allow the question carrying words capable of two-three meanings, questions having use of both past and present in one sentence, or multiple questions which is likely to confuse a witness. Where the witness seems confused instead of repetition of the same question, the court should direct for its re-phrasing.

Explanation: (i) The reaction of vulnerable witness shall be treated as sufficient clue that question was not clear so it shall be rephrased and put to the witness in a different way.

(ii) Given the witness developmental level, excessively long questions shall be required to be rephrased and thereafter put to witness.

(iii) Questions framed as compound or complex sentence structure; or two part questions or those containing double negatives shall be rephrased and thereafter put to witness.

37. Testimonial aids.-

The court shall permit a child to use testimonial aids as defined in the definition clause.

38. Protection of privacy and safety.-

(a) **Confidentiality of records-** Any record regarding a vulnerable witness shall be confidential and kept under seal except upon written request and order of the court, the record shall only be made available to the following:

- (i) Members of the court staff for administrative use;
- (ii) the Public Prosecutor for inspection;
- (iii) defence counsel for inspection;
- (iv) the guardian *ad litem* for inspection; and
- (v) other persons as determined by the court.

(b) **Protective order-** The depositions of the vulnerable witness recorded by video-link shall be video recorded except under reasoned order requiring the special measures by the Judge. However where any videotape or audiotape of a vulnerable witness is made, it shall be under a protective order that provides as follows:

- (i) A transcript of the testimony of the vulnerable witness shall be prepared and maintained on record of the case. Copies of such transcript shall be furnished to the parties of the case.
- (ii) Tapes may be viewed only by parties, their counsel, their expert witness, and the guardian *ad litem*.
- (iii) No person shall be granted access to the tape, or any part thereof unless he/she signs a written affirmation that he has received and read a copy of the protective order; that he submits to the jurisdiction of the court with respect to the protective order; and that in case of violation thereof, he/she will be subject to the contempt power of the court.

- (iv) Each of the tapes, if made available to the parties or their counsel, shall bear the following cautionary notice:

"This object or document and the contents thereof are subject to a protective order issued by the court in (case title), (case number). They shall not be examined, inspected, read, viewed, or copied by any person, or disclosed to any person, except as provided in the protective order. No additional copies of the tape or any of its portion shall be made, given, sold, or shown to any person without prior order of the court. Any person violating such protective order is subject to the contempt power of the court and other penalties as prescribed by law."

- (v) No tape shall be given, loaned, sold, or shown to any person except as ordered by the court.

- (vi) This protective order shall remain in full force and effect until further order of the court.

- (c) **Personal details during evidence likely to cause threat to physical safety of vulnerable witness to be excluded** - A vulnerable witness has a right at any court proceeding not to testify regarding personal identifying information, including his/her name, address, telephone number, school, and other information that could endanger his/her physical safety or his/her family. The court may, however, require the vulnerable witness to testify regarding personal identifying information in the interest of justice.

- (d) **Destruction of videotapes and audiotapes**- Any videotape or audiotape of a child produced under the provisions of these guidelines or otherwise made part of the court record shall be destroyed as per rules to be framed by the High Court Of Judicature at Allahabad later on.

39. Protective measures.-

At any stage in the justice process where the safety of a victim or vulnerable witness is deemed to be at risk, the court shall arrange to have protective measures put in place for the victim or vulnerable witness, as the case may be. Those measures may include the following:-

- (a) Avoiding direct or indirect contact between a child victim or witness and the accused at any point in the justice process;
- (b) restraint orders;
- (c) a pretrial detention order for the accused or with restraint or "no contact" bail conditions which may be continued during trial;
- (d) protection for a child victim or witness by the police or other relevant agencies and safeguarding the whereabouts of the child from disclosure; and
- (e) any other protective measures that may be deemed appropriate.

40. Savings.-

In case of any confusion in the interpretation of any clause of the scheme, mentioned herein above, the order of the presiding Judge shall be final and conclusive unless such order has been challenged at any higher forum.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञाप्तियां

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 1766/आठ-विभू0अ0अ0/अमरोहा—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिभूमि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) अमरोहा, राजवाहा के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम बसेरा कंजर में कुल 0.7860 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1328, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिस्ट्री कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर धनौरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम बसेरा कंजर की 0.7860 हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन एवं पुनर्वर्वस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	बसेरा कंजर	321	0.0240
				322	0.1020
				326	0.1440
				329	0.1470
				330	0.0120
				386	0.3570
				योग . .	0.7860

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"					

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा जनपद अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION*March 16, 2022*

No. 1766/VIII-S.L.A.O./Amroha—Whereas Preliminary Notification No. 1328, Dated 29-10-2021 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.7860 hectares of land in Village-Basera Kanjar, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body) and lastly published on dated 04-12-2021. The Deputy Collector Dhanaura was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.7860 hectares in Village-Basera Kanjar, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha, as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE "A"
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Amroha	Dhanaura	Dhanaura	Basera Kanjar	321	0.0240
				322	0.1020
				326	0.1440
				329	0.1470
				330	0.0120
				386	0.3570
				Total :	0.7860

SCHEDULE “B”
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6

Hectare

.....No. of Displaced Families is “Zero”

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Amroha for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

16 मार्च, 2022 ई0

सं0 1764/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिि0 अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-6, मेरठ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) अमरोहा राजवाहा एवं धकतौरा माईनर के हैड के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम अक्खा नंगला में कुल 0.9513 हेठो भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1326, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर धनौरा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील धनौरा, परगना धनौरा, ग्राम अक्खा नंगला की 0.9513 हेठो भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव का घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची “क”
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
अमरोहा	धनौरा	धनौरा	अक्खा नंगला	23	0.1820
				142	0.1404

1	2	3	4	5	6
				हेक्टेयर	
			143		0.1664
			148		0.2601
			151		0.2024
			योग.		0.9513

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
				हेक्टेयर	
				विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"	

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह० (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

March 16, 2022

No. 1764/VIII-S.L.A.O./Amroha—Whereas Preliminary Notification No. 1326, Dated 29-10-2021 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.9513 hectares of land in Village-Akkha Nangla, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha is required for public purpose, namely, Project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) through Canal construction (name of requiring body) and lastly published on dated 04 December, 2021. The Deputy Collector Dhanaura was appointed is Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of this porject affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the Section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under Section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.9513 hectares in Village-Akkha Nangla, Pargana-Dhanaura, Tehsil-Dhanaura, District-Amroha, as given in Schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabiltation and Resettlement Scheme with publication

of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE “A”
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
<i>Hectare</i>					
Amroha	Dhanaura	Dhanaura	Akkha Nangla	23	0.1820
				142	0.1404
				143	0.1664
				148	0.2601
				151	0.2024
				Total :	0.9513

SCHEDULE “B”
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6

Hectare

.....No. of Displaced Families is “Zero”

NOTE—A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Amroha for the purpose of acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

04 अप्रैल, 2022 ई०

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की अधिसूचना

सं0 1583/8(भू०अ०)/न०म०पा०—प्रथम-1/लखनऊ—लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा लखनऊ विकास प्राधिकरण से संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लिंग की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास के लिए 45 मीटर रोड के निर्माण हेतु जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, परगना लखनऊ के ग्राम सरसंवा की 0.7184 हेतु भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 1076/8(भू०अ०)/न०म०पा०-I, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थी, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची “क” में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है। तथा अनुसूची “ख” में उल्लिखित जिला लखनऊ, तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हेतु भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित मेसर्स ईमार एमजीएफ लैण्ड लिंग की इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप के सम्पूर्ण विकास के लिए जनपद लखनऊ, तहसील सरोजनी नगर, परगना लखनऊ, ग्राम सरसंवा की 0.7184 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित 45 मीटर रोड हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।)

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर					
लखनऊ	सरोजनी नगर	लखनऊ	सरसंवा	39	0.0222
				48	0.0356
				177	0.0136
				179	0.0046
				184	0.123
				185	0.0116
				186	0.0056
				274-मि0	0.1212
				275-मि0	0.210
				56	0.171
				योग. .	0.7184

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
शून्य					
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ 6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-४
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-४१
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीप्रेमेन्ट)



सरकारी गज़ाट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

01 अप्रैल, 2022 ई०

नई दिल्ली, तारीख

11 चैत्र, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-वि०प०/२/१६/२०२२-बी०ई०-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, बदायूं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के लिये सदस्य के रूप में श्री बनवारी सिंह यादव के निर्वाचन को प्रश्नाकृत करने वाली 2016 की निर्वाचन याचिका संख्या 02 श्री जितेन्द्र यादव बनवारी सिंह यादव में इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 के आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

1st April, 2022

New Delhi, dated the

11th Chaitra, 1944 (Saka).

NOTIFICATION

No. 82/UP-LC/2/16/2022-BE-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Order dated 24-12-2021 of High Court of Judicature at Allahabad in the 'Election Petition no. 02 of 2016, Shri Jitendra Yadav versus

Shri Banwari Singh Yadav challenging the Election of Shri Banwari Singh Yadav as member of the Legislative Council of Uttar Pradesh from Budaun Local Authority Constituency from the State of Uttar Pradesh.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Election Petition no. 2 of 2016.

(Under Section 80, 80-A/81 of Representation of People Act, 1951)

District : Budaun.

Jitendra Yadav,
S/o Late Shyam Singh,
R/o Village Sharfabad, Sector 72-2, Tehsil Dadri,
District Gautam Budh Nagar, U.P.

. . Petitioner.

VERSUS

Banwari Singh Yadav,
S/o Shri Lakan Singh,
R/o Village Manpur, Post Asafpur,
District Budaun.

. . Respondent.

Court No. - 39

Case :- ELECTION PETITION No. - 2 of 2016

Petitioner :- Jitendra Yadav

Respondent :- Banwari Singh Yadav

Counsel for Petitioner :- In Person, Arvind Kumar Mishra, Jitendra Yadav, K.R. Singh, N.K. Pandey

Counsel for Respondent :- Rahul Yadav, Abhilasha Singh Rahul Yadav, Vijendra Singh

Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal J.

1. Heard Sri N.K. Pandey and Sri K.R. Singh learned counsels for the election petitioner.
2. This election petition has been presented under Sections 80, 80-A/81 of the Representation of People Act, 1951 (In short as “the R.P. Act”) by Sri Jitendra Yadav (herein referred to as “the election petitioner”) who had lost in the biennial election of the Uttar Pradesh Legislative Council from Budaun Local Authority Legislative Council Constituency. The election was notified vide notification dated 29.1.2016 issued under Section 16 of the R.P. Act.
3. As per the election programme, polling was conducted on 3.3.2016. The election petitioner was a candidate of the Bhartiya Janta Party (B.J.P.) and the returned candidate was set up by the Samajwadi Party (S.P.). The election petitioner was the sitting member of the Legislative Council, Budaun Local Authority Council Constituency at the time of the election in question. The result of the election was declared on 6.3.2016 wherein the election petitioner had received 416 votes

whereas 1723 votes were obtained by the returned candidate. Out of total 2168 votes, 29 votes were declared invalid resulting into 2139 valid votes.

4. The election petition has been filed on the grounds that the returned candidate, his election agent, polling agents, workers and supporters with the consent of the returned candidate and the election agent of the returned candidate had committed corrupt practices of Booth capturing as defined under Section 123(8) readwith Section 135-A of the R.P. Act within the meaning of Section 123(2) of the Act.

It is contended that the polling agents of the returned candidate at respective polling stations with the workers, supporters and other associates of the returned candidate with his consent and that of his election agent had captured the polling booths and forcibly snatched the ballot papers from the hands of the electors who went to cast their votes and recorded the votes in favour of the returned candidate by marking '1' and, thus, committed corrupt practices within the meaning of Section 123(8) readwith Section 135-A of the R.P. Act.

The second ground is that the returned candidate, his election agent, workers, supporters and polling agents with his consent had committed corrupt practice of causing undue influence by directly/indirectly interfering in the free and fair exercise of the electoral rights of the electors of the Constituency, by extending threat and creating an atmosphere of terror by forcibly lifting the electors from their houses and keeping them at a particular place and, thus, committed corrupt practice of undue influence within the meaning of Section 123(2) of the R.P. Act.

Apart from these two grounds, it was also contended that the returned candidate, his election agent, workers and supporters with his consent and the consent of his election agent had procured and attempted to procure the assistance of the State Government servants such as the District Panchayat Raj Officer, Budaun, the Block Development Officer and other subordinate employees of the respective Kshetra Panchayat of District Budaun, who were appointed/deployed as Presiding Officers/Polling Officers at respective polling stations/booths and also the police personnel of Districts Budaun and Bareilly for the furtherance of the prospectus of the election of the returned candidate and, thus, the returned candidate had committed corrupt practices within the meaning of Section 123(7) of the R.P. Act.

5. With the above contentions, it is prayed that the election petitioner is entitled for a declaration as contemplated under Section 101(b) of the R.P. Act to seek exclusion of the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices of Booth capturing and undue influence and other corrupt practices as stated in the election petition. The reason is that the result of the election, insofar as it concerned the returned candidate has been materially affected by non-compliance of the provisions of the Constitution of India, R.P. Act, Rules and Orders framed under the R.P. Act as also the orders issued under the R.P. Act as also the orders issued by the Election Commission of India from time to time.

As a concise statement of material facts and particulars in respect of the grounds noted above, the averments have been made in paragraphs '10' onwards of the election petition.

6. Before advertig to the facts and the evidence before the Court, it may be pertinent to note here that on the presentation of the election petition, notices were issued to the returned candidate on 10.5.2016, whereafter, he had put in appearance through his Advocate on 30.6.2016. By the order dated 22.7.2016, it was directed that the copy of the election petition be provided to the counsel for the returned candidate. On filing of the application under Order VII Rule 11 C.P.C. as also the written statement by the returned candidate, vide order dated 30.9.2016, time was granted to the election petitioner to file his reply. However, before the matter could proceed further, on 20.3.2017, it was intimated by the learned counsel for the election petitioner that the returned candidate namely

Sri Banwari Singh Yadav had died on 8.3.2017. The report submitted by the District Magistrate, Budaun dated 18.3.2017 reporting the factum of death of Sri Banwari Singh Yadav before the Chief Secretary, U.P. Legislative Council Secretariat (Administration), Lucknow had been supplied in the Court. It was, thus, directed that the factum of death of the returned candidate be published in the Official Gazette as per Section 116 of the R.P. Act. The office was also directed to intimate the Election Commission of India regarding the event of death of the sole respondent and the pendency of the present election petition. As per the office report, the gazette notification dated 15.4.2017 had been issued pursuant to the above direction but no one had put in appearance to oppose the election petition. The matter had, therefore, been proceeded ex-parte. After hearing the counsel for the election petitioner, the application under Order VII Rule 11 C.P.C. has been finally decided vide order dated 9.11.2017 and the matter was posted for filing of the original documents and framing of the issues.

7. Following issues were framed vide order dated 14.12.2017 with the assistance of the counsel for the election petitioner:-

(1) Whether the returned candidate or his Election Agents, Polling Agents or Workers and Supporters had indulged in corrupt practices of Booth capturing within the meaning of Section 123(8) read with Section 135-A of the Representation of the People Act, 1951 with the consent of the returned candidate or with the consent of his Election Agent?

(2) Whether the returned candidate, his Election Agent, Polling Agents or Workers and Supporters had caused undue influence by creating an atmosphere of terror and by extending threat to the voters or by lifting them from their houses to vote and keeping them at a designated place/Farmhouse with the consent of the returned candidate or his agent, thereby interfering in free and fair exercise of electoral rights of the voters, thus, indulging in corrupt practices within the meaning of Section 123(2) of the Representation of People Act, 1951?

(3) Whether the returned candidate, his Election Agent or Workers and Supporters or his Polling Agents had committed corrupt practices of hiring and procuring assistance of Government employees on election duty for furtherance of the prospects of election of the returned candidate with his consent or of his Election Agent within the meaning of Section 123(7) of Representation of Peoples Act, 1951?

(4) Whether the votes obtained by the returned candidate by adopting such corrupt practices are liable to be excluded from counting?

(5) Whether the result of election of returned candidate is materially affected by non-compliance of the provisions of the Constitution of India, the Representation of the People Act, 1951, the Conduct of Election Rules, 1961 and orders issued by the Election Commission of India?

(6) Whether the election petitioner is entitled for declaration under Section 101(b) of the Representation of the People Act, 1951 after excluding the votes obtained by the returned candidate as a result of such corrupt practices of Booth capturing, undue influence and hiring and procuring assistance of Government employees on election duty?"

8. On presentation of the list of witnesses on each issues raised in the election petition, the counsel for the petitioner was permitted to file affidavits of the witnesses in evidence as per Order XIX Rule 1-A of the Code of Civil Procedure as the case is proceeding ex-parte. The election petitioner, however, was required to record his evidence in accordance with Order XVIII Rule 4 C.P.C. After filing of the affidavits, by the order dated 10.1.2020, in a random selection, two sets of witnesses detailed in the said order were directed to remain present in the Court on the dates fixed to corroborate their statements. The cross-examination of the witnesses present in the Court and that of

the election petitioner was completed on 14.2.2020 and, thereafter, the matter was proceeded for hearing. The hearing was, however, interrupted severely on account of set of COVID-19 and could be completed only on 2.9.2021.

9. It is pertinent to note that the evidence were led by the election petitioner only on two issues, namely issue no. (1) relating to Booth capturing and issue no. 2 pertaining to undue influence. No evidence was led on issue no. 3. Issue nos. 4, 5 and 6 are legal issues and further discussion thereon would depend upon the findings on issue nos. 1 and 2.
10. It would be apposite now to go through the pleading of the parties. The allegations with regard to Booth capturing are contained in paragraphs '40' to '51' of the election petition. Several instances have been given therein regarding the conduct of the polling agents of the returned candidate who allegedly had snatched the ballot papers from the hands of the electors who went to cast their votes at the polling stations in question and that their ballot papers were forcibly submitted in favour of the returned candidate. It is, thus, contended that the polling agents of the returned candidate had committed corrupt practices with the consent of the returned candidate.

In paragraphs '36' to '41', the allegations are of causing undue influence by the returned candidate and his election agents. It is contended therein that about 200 electors including Gram Pradhan, members of Kshetra Panchayat and Zila Panchayat, who were recorded as electors in the concerned Constituency were detained and kept at a Farmhouse situated at village Maanpur, Budaun which belonged to the returned candidate. Likewise, 250 electors were forcibly lifted and detained at Nausera Farmhouse house belonged to the returned candidate and 150 electors were forcibly detained at Zila Panchayat Kothi situated at Budaun. Thus about 900 electors were terrorized with the consent of the returned candidate and were regularly threatened by the agents of the returned candidate with his consent that if they did not cast their votes in favour of the returned candidate, they would face dire consequences. With this threatening, all the detained persons were released barely 3-4 hours before the start of the polling on 3.3.2016. The election petitioner has provided the details of about 452 such electors out of 900 alleged electors who were forcibly lifted from their houses on different dates allegedly with the help of the local police personnel and detained at different places such as Arjun Park Ram Nagar Bareilly, Farmhouse Maanpur, Budaun, Nausera Farmhouse, Budaun and Zila Panchayat Kothi Budaun. The description of these electors have been given in a chart appended to paragraph '41' of the election petition.

In paragraph '36' of the petition, it is stated that the returned candidate had held a meeting at his local residence known as Himanshu Bhawan, Shivpura, Budaun on 10.2.2016 at about 8:00 PM and prepared a plan and mechanism as to how the electors of the constituency concerned would be manipulated. It was planned that the electors would be lifted from their houses and be kept at different places and would be released only on the date of the polling. It is, thus, contended by the election petitioner that the returned candidate had given his consent to his polling agents, workers, supporters and the election agent for commission of corrupt practices and to cause undue influence on his behalf. The said meeting was attended by the persons named in paragraph '36' including the District Panchayat Raj Officer and the police personnel (named therein) deployed in the security of the returned candidates and number of workers, supporters of the returned candidate including his polling agents and musclemen and several antisocial elements. The specific instance of few of the electors who were allegedly lifted at the instance of the returned candidate has been given in paragraphs '37' and '38'. In paragraph '39' of the election petition, it is stated that though paramilitary force was deployed but in all 16 polling stations local police was deployed inside the polling stations and the police personnel being under the control of the State Government run by the Samajwadi Party at that time, they were regularly and continuously helping the returned candidate and the local police personnel inside the polling station had nullified the effect of deployment of paramilitary force at each and every polling station.

In the written statement supported by the affidavit of the returned candidate, the averments in paragraphs '36' to '41' of the petition have been denied as being false, incorrect and concocted.

In reply to paragraph '36', it is categorically stated that no such meeting was held on 10.2.2016 at the residence of the returned candidate. The allegations of the deliberations alleged to have been made in the So-called meeting were also denied. It is stated that the said averment has been made to add colour to the case of the election petitioner. In paragraph '37' onwards, it is stated that two affidavits filed by persons named as Dr. Naresh Shakya and Devendra appended as Schedule (IX) to the election petition contained identical allegations and appeared to have been manufactured for the purpose of the election petition. The averments in those affidavits have been specifically denied having been incorrect and false. It is, then stated that false and general allegations have been made without giving any specific date, time and place and the manner of each incident of alleged corrupt practice. The allegations of forcibly lifting of the electors in absence of specific date, time and place of the incident cannot be treated to be sufficient material for the purpose of establishing the case of corrupt practice against the returned candidate. The complaints of forcibly lifting of electors, their detention at alleged various places were inquired into by the district police administration and all such complaints were found to be false. In an attempt to give specific material facts and particulars in the election petition, to establish the allegations of corrupt practices, false and concocted story has been narrated. The list of 452 electors who were allegedly detained and kept at different places on different dates and time, had been denied as being false. The allegations of Booth capturing and that the polling agents of the returned candidate had snatched ballot papers of the electors and cast their votes in favour of the returned candidate had been denied as being false, vague and incorrect. It is alleged that the names of polling agents have been given in the act of snatching of ballot papers from the electors of polling station Jagat which could be easily done from the voter list itself. None of them had lodged any complaint at the time of polling before the Presiding Officer. The allegations in the election petition are not corroborated by any reliable material. Similarly the names of polling agents of different polling stations with the names of voters had been given in the election petition falsely just to give colour to the allegations of corrupt practice of snatching ballot papers from the electors. All allegations in different paragraphs of the election petition have been denied being false and concocted and it was added that no complaint of Booth capturing was made to the Presiding Officer on the day of polling and false story has been concocted after the election petitioner had lost in the election. Other allegations of involvement of the State officials to help the returned candidate had also been denied though they may not be relevant for the decision of the present petition, inasmuch as, no evidence has been led on the said issue. Lastly, it is contended that the election petitioner had failed to furnish material facts and particulars to establish the alleged corrupt practices and the pleadings are unnecessarily scandalous, frivolous and vexatious which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of election petition. No relief as such can be granted to the election petitioner and the election petition is liable to be dismissed with cost.

11. List of documents has also been appended with the written statement of the returned candidate which contains the communications of the District Election Officer to the Chief Election Officer alongwith the enquiry report of the Senior Superintendent of Police, Budaun dated 1.3.2016, regarding the complaint of the election petitioner dated 27.2.2016; the report of the Additional Superintendent of Police (Rural), Budaun dated 20.2.2016 to the Officer Incharge (Complaint), Budaun regarding the complaint of Sri Harish Shakya, District President B.J.P.; the report of the District Magistrate to the Chief Election Commissioner, U.P. dated 3.3.2016 in respect of the complaint available on Samadhan Portal moved by the election petitioner; the complaint of Mukesh son of Rajendra Singh to the Chief Election Commissioner, New Delhi bearing report of the Sector Magistrate, Ashifpur and that of the Presiding Officer; the complaint of the election petitioner to the Chief Election Commissioner, New Delhi dated 3.3.2016 bearing report of the Sector Magistrate,

Ishlamnagar; the complaint of the election petitioner dated 3.3.2016 to the Chief Election Commissioner, New Delhi bearing report of the Presiding Officer, Quadar Chowk and the Sector Magistrate; the complaint of the election petitioner dated 3.3.2016 to the Chief Election Commissioner, New Delhi bearing reports of the Sector Magistrate; the complaint of the election petitioner dated 3.3.2016 to the Chief Election Commissioner bearing reports of the Presiding Officer and the Sector Magistrate, Shahsawan; the report of the District Magistrate dated 3.3.2016 regarding the complaints available on Samadhan Portal alongwith the report of the Additional District Magistrate/Up-Nirwachan Adhikari; the report of the District Magistrate/Zila Nirwachan Adhikari dated 27.2.2016 in respect of the complaint of Sri Harish Shakya, District President, B.J.P. dated 17.2.2016 alongwith the report of the Senior Superintendent of Police dated 28.2.2016 containing the detailed enquiry report and the complaint; the report of the Up-Zila Nirwachan Adhikari Badaun dated 3.3.2016 to the Chief Election Commissioner, U.P. in respect of the complaint letter dated 3.3.2016 of the election petitioner on Samadhan Portal; the report of the District Magistrate dated 3.3.2016 pertaining to complaint of the election petitioner regarding allegations of forcibly lifting of the electors and their detention alongwith the report of the Senior Superintendent of Police, Budaun dated 2.3.2016; the joint report dated 2.3.2016 of the Circle Officer and Up-Zila Adhikari, Sadar; the letter of Officer Incharge, as also the letter of the observer dated 1.3.2016 on the complaint of the election petitioner; the report of the District Magistrate dated 3.3.2016 to the Chief Election Commissioner, U.P. in respect to the complaint of the election petitioner regarding allegations of building pressure on the electors and allegations of Booth capturing. The enquiry reports of the District Magistrate and the communications made by him on various dates with regard to several complaints lodged by the election petitioner on Samadhan Portal; the report of the District Magistrate dated 1.3.2016 on four points including the complaint of Naresh Shakya pursuant to the telephonic conversation with Vishesh Karya Adhikari, the Chief Election Commissioner, U.P.; the report of the Up-Zila Adhikari, Budaun dated 20.2.2016 to the Additional District Magistrate, Budaun regarding the complaint of the District President, B.J.P. for alleged harassment of Naresh and Mahendra Singh, B.D.C. members alongwith the statement of Smt. Sunita wife of Mahendra Pal and that of Smt. Saroj wife of Sri Naresh; the reports of Up-Zila Adhikari Sahaswan dated 19.2.2020 to the District Nirwachan Adhikari in relation to Ex-B.D.C. member Naththu Ram alongwith statement in writing of his sons Pappu and Charan Singh. Diaries of the Presiding Officer of the polling stations.

It may be pertinent to note at the outset that the above noted documents were sought to be filed by the returned candidate in order to answer the allegations made by the election petitioner regarding Booth capturing and undue influence and participation of the officers of the District Administration and Police Authorities in favouring the returned candidate.

We may note that these documents could not be filed by him as before the matter could be proceeded, the returned candidate had died unfortunately. These documents, however, could have been obtained by the election petitioner from the office of the concerned authority but none of them have been filed as the contention of the counsel for the election petitioner was that the district authorities namely the police administrative authorities were under the influence of the returned candidate and hence they did not pay heed to the complaints of the election petitioner and other electors.

12. In the list of documents filed by the election petitioner exhibited as Exhibit 'P-1' to Exhibit 'P-17', the certified copy of the final result sheet, the list of polling stations, the list of Presiding Officer/Polling Officer, the electoral roll-2016, the extract of handbook for returning officer and the complaints and the representations of the election petitioner alongwith the affidavits of Sharad

Gupta, the polling agent of the election petitioner at polling station Dahgawan, the affidavit of Naresh Shakya and Dharmendra Shakya (polling agent of Quadar Chowk), the representation of Harish Shakya, District President, B.J.P., the affidavit of Mukesh son of Rajendra dated 4.3.2016 sent to the Election Commissioner of India, photo copy of the Public Interest Litigation (PIL) No. 8156 of 2016 filed by Dr. Naresh Shakya and the order passed thereon have been filed alongwith the several other representations and complaints in support of the allegations in the election petition as noted above. Apart from the documentary evidences, oral evidence in the nature of affidavits of the witnesses in examination-in-chief have been filed. From the list of total 81 witnesses dated 25.10.2018 was filed in the Court, 21 witnesses had been directed to appear to corroborate their statements who had appeared and were cross-examined by the Court.

13. The submissions in brief of the learned counsel for the election petitioner are that from the material particulars given in the election petition and the evidence in the shape of documentary and oral evidence of polling agents and electors, who are independent persons, it has been proved by the election petitioner that the polling agents of the returned candidate took the polling stations completely in their control and allowed to vote only those persons who were supporters of the returned candidate and prevented the others from free exercise of their right to vote, which amounts to Booth capturing within the meaning of Sections 128 and 135-A(b) of the Act. The aforesaid corrupt practice was committed with the consent of the returned candidate. There is evidence of the meeting called by the returned candidate prior to the date of poll to instruct his polling agents to ensure that the votes were cast in his favour and to frame the strategy to capture the Booth.

It is contended that on the date of polling also, the returned candidate had visited the polling stations and directed his polling agents personally to snatch the ballot papers from the electors who deny to vote for him and marked their ballot papers in favour of the returned candidate. It is contended that the statements in the examination-in-chief of PW-12, PW-14, PW-17, PW-19, PW-20 and PW-21 and their cross examination as also the affidavits in examination-in-chief filed as paper no. 'A-21' to paper no 'A-76' are in support of the pleadings of corrupt practices of Booth capturing contained in paragraph nos. '40' to '51' and pertaining to corrupt practice of undue influence in paragraph nos. 36 to 41.

It is contended that the credible evidence furnished by the election petitioner in the shape of the affidavits of the electors and polling agents and by presenting them in the Court for cross-examination, cannot be brushed aside only for the fact that no first information report was lodged by the electors or the polling agents or any other candidate.

14. It is argued that in view of the provisions of Section 28-A of the R.P. Act, 1951 and Article 324 of Constitution of India, all the powers of the district and police administration vests in the Election Commission of India from the date of notification of the election till the completion of the application. The Chief Electoral Officer of the State, the District Election Officer, the Returning Officer, the Assistant Returning Officer and the Presiding Officer, the Polling Officer and other officers deployed for the purpose of polling and counting of votes and conduct of election worked under the control and supervision and direction of the Election Commission of India from the date of the notification of the election till completion of the election. In view of the Model Code of Conduct being issued by the Election Commission of India, effective from the date of notification of election, any complaint brought in the notice of the Returning Officer, the Assistant Returning Officer, the Presiding Officer, Polling Officer, Observer or any other Officer deployed by the Election Commission of India or any other complaint relating to the election was to be dealt with by the Election Commission of India to take appropriate action against the concerned person or authority. It was the duty of the Election Commission of India, the Presiding Officer, the Polling Officer or the Returning Officer to lodge first information report in the concerned police station in

case of any violence or electoral offence as mentioned in Chapter III of the R.P. Act. For the fact that the election petitioner or any elector had not registered a first information report for forcibly snatching the ballot papers of electors at a particular polling station, it cannot be said that the incident of Booth capturing or undue influence did not happen. The election petitioner sent representations to the Election Commission of India on its e-mail address and through FAX prior to and on the date of polling bringing to its notice about the circumstances of terror and fear created by the returned candidate and his workers and supporters with the help of police and district administration and commission of corrupt practices of Booth capturing and undue influence during polling on 3.3.2016.

15. It is contended that in spite of the representations given by the election petitioner, the Presiding Officer, Polling Officer, Observer or the Returning Officers or even the Election Commission of India did not take any effective step to prevent the abuse of election process nor any FIR was registered or any disciplinary action was taken against the erring officers. The polling was not held in free, fair and transparent manner on 3.3.2016. It is stated that the statement of the polling agent of the election petitioner deployed at the polling station block Jagat namely PW-2, Rajesh Kumar Singh Shakya about the Booth capturing is corroborated by the evidence of independent witnesses namely the electors who had appeared in the witness box as PW-10 and other electors whose statements are on record in the shape of their affidavits. It is not relevant as to from where and when the electors were lifted but the question is as to whether they were actually lifted and detained at a particular place which is proved from the evidence of PW-10 who remained intact in his cross-examination. Similarly, the statement of other witnesses produced by the election petitioner in support of the pleadings in paragraph nos. '44' to '51' relating to corrupt practice of Booth capturing by the polling agents of the returned candidate are intact during the course of their cross examination. The factum of Booth capturing and undue influence, therefore, with the consent of the returned candidate are proved by cogent evidence put forth by the election petitioner. The statements of electors who are independent witnesses cannot be brushed aside as they remained intact during the course of cross examination made by the Court itself.
16. Having heard learned counsel for the election petitioner and perused the record, in the light of the pleadings and the evidence put forth by the election petitioner in support of his allegations of Booth capturing and undue influence to materially affect the result of the election, one fact reflected from the record is pertinent to be noted at the outset.
17. It has been brought on record that one Dr. Naresh Shakya son of Bhupal Shakya, residence of Gariya Muttalika, Noorpur, Block Quadar Chowk, Budaun had filed a Public Interest Litigation (PIL) No. 8156 of 2016, copy of the petition has been filed in the documentary evidence and marked as Exhibit P-17. The said petition was supported by affidavit of one Amit Kumar Singh, member of Block Development Council (BDC) and elector in the election in question from the constituency concerned. It was stated therein that the petitioner namely Dr. Naresh Kumar Shakya a member of Block Development Council and the elector (voter) for the election of M.L.C. of the constituency Budaun had filed the Public Interest Litigation on behalf of the electors who were looking forward to cast their votes in favour of candidates of their choice without any threat, to ensure the election being held in a free and transparent manner. It was stated that some anti-social elements including the local police were extending help to the candidate namely Banwari Singh Yadav (now returned candidate) and the police personnel were visiting the house of the electors accompanied by anti-social elements at the behest of the said candidate. The District President of B.J.P. namely Harish Shakya had also moved application on 16.2.2016 to the District Election Officer and the Chief Election Officer to take effective steps to ensure holding of elections without any threat or

harassment of the voters. It was stated that the candidate namely Banwari Singh Yadav being the candidate of the ruling party, even the district administration and the police officials were acting at his instance with his connivance.

It was further stated that the petitioner therein namely Dr. Naresh Shakya was apprehended from his house by the local police on 12.2.2016, in order to detain him so that he may not tender his vote in the election and that he was still in the police custody though no criminal case had been registered against him. It was pleaded that an application dated 17.2.2016 was moved by the father of the petitioner before the District Election Officer and the Presiding Officer and the Chief Election Commissioner praying for immediate relief of his son and taking appropriate action against the erring officials. The copy of the said application was appended as Annexure '5' to the said writ petition.

A perusal of the said application indicates that the same was allegedly received in the office of the District Election Officer on 17.2.2016 itself. The affidavit in the said writ petition of the deponent was sworn on 18th February, 2016, a day after the application was allegedly moved by the father of the petitioner namely Naresh Shakya to report about the illegal detention of his son.

18. Alongwith the present election petition, a letter dated 26.2.2016 written by Naresh Shakya, the petitioner in the aforesaid PIL, has been appended at page '166' in support of the averments in paragraph '37' of the election petition. The said letter was written on the subject "with regard to the compliance of the judgment/order dated 23.2.2016 passed by the Hon'ble High Court in PIL No. 8156 of 2016". In the said letter addressed to the Chief Election Commissioner, Election Commission of India, New Delhi, it was stated that after filing of the nomination of the Samajwadi Party candidate, most of the Government servants of Panchayat Raj Department as well as police department were working as workers and supporters of the Samajwadi Party candidate. Consequently all the voters in the said election had been terrorized by the Government servants. One Mr. Rajesh Yadav, District Panchayat Raj Officer (DPRO), Budaun who are also having charge of two blocks (Sahaswan and Ishlarnagar) was continuously calling the B.D.C. members as well as Pradhans (who were electors in the said election) to tell them to cast their votes only in favour of Samajwadi Party candidate or else they would face adverse consequences (enquiry). The directions of the Hon'ble High Court in the judgment and order dated 23.2.2016 were extracted, thereafter, and it was prayed therein that steps be taken to ensure free, fair and impartial election and to curb the illegal activities of the Samajwadi Party candidate.

It was, then, stated that:-

"1. At all the polling centers central forces should be deployed on the day of poll (03-03-2016) and same shall also be video graphed otherwise there is lest possibility free, fair and impartial election and the local police kept away from the election.

2. The DPRO Mr. Rajesh Yadav ought to be immediately transferred from the Distt. Budaun and take suitable legal action against him to ensure free, fair and impartial MLC (Local Bodies) 2016 of Budaun UP.

3. The helpers require to the voters should be their blood relation as required in law otherwise there every possibility the voters will under the threats of Samajwadi party candidate and their supporters.

4. As per information of the applicant many voters have been kept under the custody of Samajwadi party candidate at his farmhouse situated at Manpur as well as some voters were kept at Ramnagar, Faizganj Behta and Mau Ramnagar Situated at Arjun Park Aonla, Unnapur Police Station Ramnagar of Distt. Bareilly. under the supervision police of Distt. Budaun it may be inquired. Suitable action may also be taken to free the voters from custody of Samajwadi party

candidate so the voters may be participated as per their choice to ensure the free, fair and impartial MLC (Local Bodies) 2016 of Budaun UP."

A careful reading of the above representation made by the petitioner namely Naresh Shakya after order in the PIL (noted above), it is evident that there was no whisper of his detention by the police authority in order to restrain him to cast his vote as alleged in the PIL.

19. A perusal of the order passed by the writ Court further indicates that the petitioner was granted liberty to bring his specific grievances to the attention of the Election Commission of India who had been vested with the power of superintendence, direction and control over the elections.
20. Another undated representation given by the petitioner namely Dr. Naresh Shakya in 'Hindi' had also been appended at pages '168' and '169' of the election petition. The photo copy of the affidavit of Naresh Shakya dated 4.3.2016 has been filed in documentary evidence and is exhibited as Exhibit 'P-11', copy of which has also been appended with the election petition at page '176'. Paragraph nos. '4', '5', '6' and '7' of the said affidavit is relevant to be extracted hereunder:-

"4. यह कि दिनांक 12-02-2016 को स0पा0 के प्रार्थी को स0पा0 के प्रमुख क्षेत्र पंचायत कादरचौक श्री कौशल व सतीश गुप्ता थाना कादरचौक की पुलिस ने घर से जबरन उठा लिया और गाड़ी में डालकर अर्जुन पार्क रामनगर बरेली ले जाकर बन्द कर दिया।

5. यह कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमती सरोज का वोट, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में डालने के उद्देश्य से उक्त व्यक्तियों व पुलिस ने प्रार्थी को घर उठाकर उक्त स्थान पर ले जाकर बन्धक बनाया था प्रार्थी के पिता द्वारा शिकायत करने पर प्रार्थी को छोड़ एवं पुनः दिनांक 26-02-2016 को बन्धक बना लिया और प्रार्थी दिनांक 03-03-2016 को पत्नी का मतदान कराने बाद छोड़ा प्रार्थिनी को धमकी दी यदि वोट स0पा0 प्रत्याशी के पक्ष में नहीं दिया तो मेरे पति की हत्या कर देंगे।

6. यह कि इस प्रकार उपरोक्त चुनाव में प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस द्वारा औपचारिकतायें निभाई गयी हैं एवं स0पा0 प्रत्याशी को पक्ष में जबरन वोट न डलवाये गये हैं उक्त चुनाव निष्पक्ष स्वतन्त्र व पारदर्शी नहीं हुआ है।

7. यह कि मुझे बन्धक बनाकर रखा उस जगह पर अर्जुन पार्क रामनगर बरेली करीब 400-450 मतदाताओं को बन्धक बनाकर रखा जिसकी 8 पुलिसकर्मी को तैनात कर रखा था।"

21. Having perused the evidence adduced by the election petitioner in the shape of affidavit of Dr. Naresh Shakya, the representation and the PIL filed by him, it is evident that this elector who came in support of the election petitioner herein had changed his stand from time to time. As per his contention in the election petition, he was lifted by the police personnel of Quadar Chowk police station from his house on 12.2.2016 and was detained in Arjun Park, Ram Nagar, Bareilly. It is not known as to how this person had managed to file a Public Interest Litigation raising the cause of the electors before this Court on 18.2.2016 while being in the alleged illegal detention of the returned candidate at a place known as Arjun Park Ram Nagar, Bareilly. In the affidavit dated 4.3.2016, this elector stated that he was released after a complaint was made by his father, but was again detained on 26.2.2016. This statement came for the first time in the notary affidavit prepared on 4.3.2016, after conclusion of the polling on 3.3.2016. The statement with regard to the alleged detention of this elector though was made before this Court in the PIL but there was no whisper of the same in the representation dated 26.2.2016 made by him to the Chief Election Commissioner. The statement in the said representation was only that as per the information of Mr. Naresh Shakya, many voters had been kept under the custody of Samajwadi Party candidate (returned candidate) at his Farmhouse situated at Manpur as well as some voters were kept at Ram Nagar, Faizganj Behta and Mau Ram Nagar situated at Arjun Park Aonla, Unnapur, Police station Ram Nagar of District Bareilly, under the supervision of police of the District Budaun. The prayer was that an enquiry be

made and suitable action be taken to free the voters from the custody of the Samajwadi Party candidate so that they may participate in the election to elect a candidate of their choice, i.e. to ensure free, fair and impartial election. It is, thus, evident that there was no statement of the alleged illegal detention of Dr. Naresh Shakya in his representation made to the Chief Election Commissioner prior to the conduct of polling. The affidavit dated 4.3.2016 appears to be a result of afterthought. There is nothing on record to corroborate statement of this elector (Dr. Naresh Shakya). There is no affidavit of Dr. Naresh Shakya in the election petition to corroborate the documentary evidence brought on record by the election petitioner.

22. It is pertinent to note that alongwith the written statement filed by the returned candidate, in the list of documents, the reports of the concerned administrative and police authority on the complaints filed by the electors including Dr. Naresh Shakya has been mentioned. There is a reference of the report of the Additional Superintendent of Police (Rural) addressed to the Officer Incharge (Complaints) regarding the complaint of Bhupal Shakya father of Dr. Naresh Shakya relating to the allegations of harassment of Dr. Naresh Shakya alongwith the report of the Circle Officer, Ujhani, the complaint, the direction of Incharge Complaints and the Senior Superintendent of Police to enquire into the matter. There is also a reference of the report of the Up-Zila Adhikari, Budaun dated 20.2.2016 submitted to the Additional District Magistrate, Budaun regarding the alleged harassment of Dr. Naresh Shakya on the complaint of the District President, B.J.P. namely Mr. Harish Shakya alongwith the statement of wife of Dr. Naresh Shakya. There is reference of several such reports in the list of documents submitted by the returned candidate. These reports appears to have been prepared and submitted to the competent authority on the complaints made by the electors including the election petitioner. None of the said reports have been brought on record of the present election petition. The bald assertion of the election petitioner that nothing had been done by the Administrative Authorities though the complaints regarding lifting of the electors and Booth capturing had been registered before them, therefore, is found absolutely false.

The election petitioner was also cross-examined by the Court on the issue as to whether he has filed the copy of the PIL instituted by Dr. Naresh Shakya and his affidavit in the documentary evidence after verification of the facts narrated therein. On the said questions, he has simply denied that he did not know anything about the statements in the PIL. The result is that he did not verify the factum of truth of the allegations at his own ends and simply filed the copy of the PIL and affidavit of Dr. Naresh Shakya on the allegations that he was lifted and detained on the instructions of the returned candidate, in the documentary evidence without verification of facts. The election petitioner has further stated that the information regarding filing of the writ petition by Dr. Naresh Shakya was got by him from the office of the District Magistrate when he reached there. It is, thus, evident from the documentary evidence and oral evidence that the allegations pertaining to the alleged harassment of Dr. Naresh Shakya, i.e. that he was lifted by the local policemen at the behest of the returned candidate could not be found proved.

Apart from Dr. Naresh Shakya, the affidavits of other electors have also been filed in support of the pleading on the allegations of Booth capturing and lifting of the relatives or the electors in order to put pressure on them to cast their votes in favour of the returned candidate. Some of the electors namely Smt. Kalawati has been examined as PW-12 who states that her husband was lifted by the workers and supporters of the Samajwadi Party (S.P.) candidate and he was detained for 15 to 20 days at a place known as Arjun Park Ram Nagar Bareilly. She then stated that when she went to cast her vote, but her ballot paper was snatched by the polling agent of the Samajwadi Party candidate and her vote was entered in favour of the returned candidate against her wishes. In cross examination, when it was asked as to whether she is an elected Gram Pradhan, PW-12 has stated that she had won the election of Gram Pradhan but was discharging duties of Gram Pradhan on the instructions of her son since after the death of her husband. She

further stated that she remains busy in her household work during day time. PW-12, however, stated that she was well aware of the work and responsibility of the Gram Pradhan. On a query made by the Court as to with whom she had come to depose in the Court, her reply was that many people had come and she came alongwith them.

23. Considering the statement of PW-12 in the examination-in-chief and the cross-examination, she does not appear to be an independent witness. It is also difficult to believe that the elected Gram Pradhan could not lodge complaint to the police about abduction of her husband for about 15 to 20 days. From her statement in the cross-examination, it is evident that she came to depose before this Court on the instructions of someone else and it was not her independent decision. All other persons who had come alongwith her as per her own submission as also the election petitioner may have influenced her decision of submitting statement in favour of the election petitioner. The statement of this witness cannot be accepted as a proof of allegations of Booth capturing and undue influence so as to set aside the election of the returned candidate.
24. Likewise, PW-9, PW-10, PW-11, PW-13, PW-14, PW-15, PW-16, PW-17, PW-19 and PW-20, who have been cross-examined by the Court are electors who were either elected B.D.C. members or Gram Pradhan.

PW-9 has stated that she went to the police station alongwith husband at about 10:00 AM and after entering her signature in the register on the instructions of the polling officer, she had received ballot paper. However, the polling agent of Samajwadi Party candidate namely Sri Rakesh Gupta had snatched the ballot paper from her and entered her vote in favour of the returned candidate. In the examination-in-chief though she has stated that she made an objection but the Presiding Officer did not pay heed and stated nothing could be done, thereafter. She then made an oral objection to the agent of B.J.P. candidate but his voice was also not heard. PW-9 stated that she intended to cast vote in favour of the election petitioner. In the cross-examination, specific question was put as to what was her action after her ballot paper was snatched, her reply is that she did not do anything as no one was there to pay heed to her complaint.

PW-10, Shankar Lal deposed in his examination-in-chief that she was lifted by the supporters of the Samajwadi Party candidate about two weeks prior to the polling and was kept at different places such as Kothi Maanpur, Nausera Farmhouse and lastly Arjun Park Ram Nagar, Bareilly. He was instructed to cast his vote in favour of returned candidate and on the date of polling, he was brought to the polling station block Jagat in a Jeep from Arjun Park Bareilly when he had received his ballot paper on the polling Booth, which was snatched by the polling agent of the Samajwadi Party candidate. Because of the entire sequence of event, he was so terrified and he could not make any complain to anyone. In the cross-examination, this witness was questioned as to whether he had given information to his family members about his abduction and illegal detention. He has simply replied that nothing could be done even by his family members because of the Ruling Party. In his affidavit in the examination-in-chief, though he has stated that he was lifted from his house but in the cross-examination, he has stated that he was lifted from his agricultural field. There is contradiction in the statement of this witness and his version in the examination-in-chief does not seem to be independent. A casual statement has been made regarding his lifting and detention by the supporters of the returned candidate. This witness could not even specify the place wherefrom he was lifted forcibly. No complaint whatsoever has been made by him or his family members about his illegal detention, which according to him lasted for fifteen continuous days.

PW-11 Jagwati stated that her ballot paper was snatched by the polling agent of the returned candidate. In the cross-examination, she was asked as to how her ballot paper was snatched, she replied that there was a lot of crowd when she went to cast her vote and in that commotion her ballot paper was snatched and she was told that her vote had been entered. She was also asked as to why she did not make any complaint to anyone, her reply was that though she agitated but no one heard her.

PW-13 Chiraunji Lal is the witness of allegations of undue influence and threatening by the workers and supporters of returned candidate. PW-13 was an elected Gram Pradhan. He has stated that polling agent of the Quadar Chowk polling Booth namely Dharmendra Kumar Shakya was already taken in the police custody and there was no occasion for him to make any complaint regarding snatching of his ballot paper. However, he gave information to the election petitioner about the said fact.

PW-14, Smt. Lakshmi also stated that her ballot paper was snatched by the polling agent of the returned candidate, she made a complaint but no one paid heed.

PW-15, Smt. Omwati stated that her son was lifted for 13 days prior to the polling, who however, returned back within 4 days.

The contention is that her son was lifted in order to put pressure upon her to cast vote in favour of the returned candidate. On the date of polling, i.e. 3.3.2016, she went to the polling station, block Quadar Chowk alongwith her younger son to cast her vote. The polling officers had instructed her to enter "1" in the ballot paper as against the name of the returned candidate. Later her ballot paper was snatched and her vote was entered in favour of the returned candidate, when she protested, she was shun away.

PW-16 and PW-17 have alleged that they were lifted and illegally detained and were brought to the polling station from the place of detention where their ballot papers were snatched and their votes entered in favour of the returned candidate. Both these witnesses were asked as to why they did not raise any protest being the responsible members of the village Panchayat and having held positions of Sadasya Kshetra Panchayat and B.D.C. member. They had not been able to give any reply to the said query. When asked, they admitted that they did not make any effort to meet any officer raising their complaint regarding illegal detention or undue influence.

PW-19 who was a Sabhasad (सभासद) had stated that her ballot paper was snatched and when she made complaint, police personnel threw her out.

PW-20 is a B.D.C. Member and stated that she and her husband both were forcibly lifted and kept under detention in Kothi Maanpur alongwith other voters. On the date of the polling, she was brought to the polling station when she was told that her vote was entered in favour of the returned candidate. In cross-examination, she stated that she was kept under detention for two days and 4-5 persons came to lift her.

25. From the statements of the electors, the witnesses noted above, it is evident that almost all of the electors who claimed to have been lifted and detained in order to put pressure upon them or whose ballot papers were allegedly snatched did not lodge any complaint either at the polling station or before any Administrative Authority, who was the Incharge of holding of the election. None of them had made complaint that their voting rights had been infringed. The electors were all either the sitting Gram Pradhan or B.D.C. members and some of them were even Corporators (सभासद). It is difficult to believe that such persons who were holding influential positions were so helpless or threatened that they did not assert themselves at all before any of the authority/Incharge of the elections. The independence of these witnesses is also doubtful. Similar allegations have been made by the other electors who have filed affidavits in the examination-in-chief in support of the election petitioner. The statements of these persons are almost similar and all of them have come forward to assert the allegations of booth capturing for the first time in the present election petition.

The contention of the counsel for the election petitioner that all the electors are independent persons and their statements being in favour of the election petitioner, no other enquiry is required, is found unsustainable.

26. Apart from the above, PW-1 to PW-8 and PW-18 are the polling agents who have been produced to prove the charge of Booth capturing by the polling agents of the returned candidate. In their affidavits, they have asserted that the ballot papers of many electors had been snatched by the polling agents of the returned candidate at different polling stations, wherein they were posted and the votes were entered in favour of the returned candidate.

27. On a query of the Court as to whether they had informed about booth capturing to any of the administrative officials, the reply of all these persons was simply 'No'. They tried to assert that they were not in a position to give information to the administrative officials as they were all under the influence of the returned candidate.

28. From the careful reading of the statements of these polling agents, it is evident that they were all been assigned the duty to ensure that no untoward incident occurred during the course of election.

PW-18 Dharmendra Shakya who was the polling agent of the election petitioner was in active politics. He remained a member of the Zila Panchayat and was also elected as the Member of Legislative Assembly (M.L.A.) as a candidate of Bhartiya Janta Party (B.J.P.) in the year 2017. It is difficult to believe that a person having such a background being the polling agent could not make a complaint with regard to the Booth capturing. It is further relevant to note that PW-18 in the cross examination has admitted that he had political rivalry with the son of the returned candidate. The bald allegations of the polling agents of booth capturing by snatching of ballot papers of the electors, therefore, is not believable.

29. At the cost of the repetition, it is pertinent to note that the polling agents who were produced to depose the allegations of Booth capturing, i.e. of snatching of ballot papers by the polling agents of the returned candidate admitted that they did not even give any intimation or complaint regarding the Booth capturing and gave intimation only to the election petitioner or the agent of the election petitioner when the polling was over. It is difficult to believe that the electors who were holding the positions of Gram Pradhan, B.D.C. member and were assigned the task of looking after the complaints of the villagers were so helpless that they could not approach the District Administrative Authority or the police for asserting their own voting rights. The allegations in the election petition that 900 B.D.C. members, Gram Pradhans and Sabhashads were forcibly lifted from their houses and detained at different places by the returned candidate could not be proved from the bald statements on the affidavits of the electors and the polling agents filed before this Court.

30. As regards the documentary evidence noted above, enquiries were made by the concerned officers such as the District Magistrate and the Senior Superintendent of Police on the complaints which have been filed in evidence in the present election petition. The copy of not a single such report has been brought before the Court so as to give a clear picture as to what had actually happened on the date of polling, i.e. 3.3.2016. As noted above, the independence and impartiality of the electors produced before the Court is doubtful as almost all of them had baldly denied the question put by the Court and could not specify as to why they did not make any complaint before the administrative authority when their ballot papers were snatched or they and/or their relatives were lifted. Almost all of them have only stated that they were power less and could not do anything as the entire District administration was under the influence of the Samajwadi Party leader, i.e. the returned candidate.

31. The Court may also take note that the returned candidate is not alive. The loyalty of the voters on the death of the returned candidate may also change as they do not remain answerable to the person in favour of whom they had submitted their votes.

32. In the light of the above material facts and on consideration of the evidence on record, both oral as well as documentary, this Court finds that the allegations of Booth capturing and undue influence to challenge the election of the returned candidate could not be proved by the election petitioner. Booth capturing is a serious offence and mere assertion in the election petition of the allegation or instances of Booth capturing by bringing the electors before this Court would not be sufficient to prove the same. The participation of Officers of the State Department such as District Administration and the police personnel though alleged in the election petition but could not be proved and the issue framed in this respect has not been pressed nor any evidence has been lead on the same.

33. From the conspectus of the evidence on record, in light of the pleadings of the parties, we do not find it a fit case for interference.

The decisions relied upon by the learned counsel for the election petitioner are distinguishable in the facts and circumstances of the present case.

No case for interference as such is made out.

The election petition is, dismissed, accordingly.

(Sd.) SUNITA AGARWAL, J.

Order Date : 24.12.2021

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।



सरकारी गज़ाट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 16 अप्रैल, 2022 ई० (चैत्र 26, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सूचित करता हूँ कि मैं कौशलेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामव्यास सिंह मेरी पार्टनरशिप फर्म फेथ इंडिया स-240/35 शिव नगर, कालोनी, टकटकपुर, वाराणसी जिसके पार्टनर वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र जर्नाधन सिंह का देहान्त दिनांक 28 जनवरी, 2021 को हो गया है जिनकी हर जगह इस फर्म में नये पार्टनर अभिषेक सिंह पुत्र कौशलेन्द्र सिंह, जी०टी० रोड, कूदरा जिला कैमूर भभुआ, बिहार, दूसरे पार्टनर के रूप में जुड़ गये हैं एवं सुरेश सिंह चौहान पुत्र रघुराज सिंह चौहान निवासी-139/3 वैभव नगर ताजगंज, आगरा स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

साझेदार,
कौशलेन्द्र सिंह।

थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 25 मार्च, 2022 को फर्म में एक नया साझेदार नूर मोहम्मद शामिल किया गया है फर्म के दो साझेदार नसीर अहमद, जबूर अहमद फर्म से अपनी स्वेच्छा से दिनांक 25 मार्च, 2022 को अवकाश ग्रहण करके अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों को सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है। किसी प्रकार का साझेदारों का फर्म पर या साझेदारों पर तथा फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं रह गया है, अब फर्म में कुल 2 साझेदार अजय पाल सिंह, नूर मोहम्मद हैं। फर्म में एवं साझेदारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी हैं।

अजय पाल सिंह,
साझेदार,
मेसर्स सिंह इन्टर प्राइजेज, बरेली (उ०प्र०)।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स सिंह इन्टरप्राइजेज, विलेज कतरोई बुजुर्ग, पोस्ट बड़ा गांव, तहसील आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उ०प्र०, पिनकोड-243303 (पंजीकरण संख्या : BAR/0004597) फर्म में 3 साझेदार अजय पाल सिंह, नसीर अहमद, जुबूर अहमद

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-विनोद आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, कार्यालय 41 ओ-ब्लाक, सब्जी मण्डी, किदर्वई नगर, कानपुर के पते से पंजीकृत है। जिसका पंजी०स० K-9498 पर दिनांक

सूचना

14 दिसम्बर, 2010 को पंजीकृत है। साझीदारी डीड मिश्रा, श्री गौतम आनन्द मिश्रा, श्रीमती ऊषा मिश्रा दिनांक 01 दिसम्बर, 2010 के अनुसार फर्म में श्री विनोद साझीदार हैं।

कुमार मिश्रा, श्री यतीन्द्र कुमार मिश्रा, श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, श्री जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, श्री राजीव कुमार मिश्रा, श्री रवि कुमार मिश्रा, श्री सौरभ मिश्रा साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को साझीदारी में श्री गौतम आनन्द मिश्रा, श्रीमती रत्ना मिश्रा, श्रीमती ऊषा मिश्रा, श्रीमती पारुल मिश्रा को शामिल किया गया है तथा उसी दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से साझीदार श्री विनोद कुमार मिश्रा, श्री यतीन्द्र कुमार मिश्रा, श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, श्री राजीव कुमार मिश्रा, श्री रवि कुमार मिश्रा साझीदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं तथा 01 अप्रैल, 2015 को फर्म का पता परिवर्तन कर जी०टी० रोड, ग्राम पो० शिवराजपुर, तह० बिल्हौर, जिला कानपुर-209205 कर दिया गया है। भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के अनुसार फर्म की भागीदारी से श्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा, श्रीमती रत्ना मिश्रा, श्रीमती पारुल मिश्रा, श्री सौरभ मिश्रा स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं और अब वर्तमान में श्री जीतेन्द्र कुमार

पार्टनर।

जीतेन्द्र कुमार मिश्रा,

सूचना

फर्म मेसर्स गोपी किशन एण्ड संस 3/29 अयोध्यापुरी समद रोड अलीगढ़ पत्रावली संख्या एजी/11991 में दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को श्री आनन्द स्वरूप केला पुत्र श्री विहारी लाल केला निवासी-श्रीकृष्णा अयोध्यापुरी समद रोड अलीगढ़ फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक हुये। वर्तमान में फर्म में भागीदारी राजेश कुमार अग्रवाल एवं राकेश कुमार अग्रवाल हैं।

राजेश कुमार अग्रवाल,
साझेदार,

में० गोपी किशन एण्ड संस,
3/29 अयोध्यापुरी समद रोड,
अलीगढ़।